state that the probe using remote sensing satellites and other methods have indicated rapid decline in glacial waters due to environmental reasons including the global warming.

FINANCIAL EXPRESS : May 15, 2005

Paying a costly price

The Naokuchia lake situated 24 km from Nainital in Uttaranchal has become second in the list of pollution in the region and is said to be a victim of the 'myopic vision of administration'. Naokuchia Tal, the deepest (135ft) and most beautiful lake of the region with its most irregular shape and nine corners is only one in the entire central Himalayan having a natural lotus-biomass, now is one of the most polluted lake of the region. Recent findings of experts entrusted with the responsibility to test the waters of the lakes of this region at the reported project cost of Rs. 46 lakh under a scheme of national project for the conservation of lakes reveal this. Besides the biochemical oxygen demand indicative of the biodegradable matter in water phosphorous, fluoride and nitrogen contents are said to be increasing in the lake of which the water is supplied to the neighbouring villages without any treatment. A considerable reduction of water volume in the biomass area, the seeds of a fish called grass carp were put into it. Almost the entire biomass was consumed by this piscine-stock and for years there were no lotus plants to be seen.

Rajshekhar Pant for SAHARA TIME : May 21, 2005

Hindi Section

बागवानी के भविष्य पर संकट के बादल

सूबे की मिट्टी में आवश्यक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं। गेहूँ, धान, तिलहन आदि मुख्य फसलों तथा फलों के बेहतर उत्पादन के लिए जिन आवश्यक पोषक खनिज तथा अणु पोषक खनिज तत्वों की जरूरत होती है, उनका प्रतिशत सिलसिलेवार घट रहा है। जैविक तथा माइक्रोबियल घटकों के लिहाज से भी मिट्टी में चिंताजनक ढंग से कमी आई है। सूबे के फल पट्टी क्षेत्रों में बोरॉन तथा मोलीब्डीनम जिस तेजी से कम हो रहे हैं, उसने बागवानी के भविष्य पर भी चिंता के बादल गहरा दिए हैं। भू–वैज्ञानिक इस स्थिति के लिए सूबे की कृषि के पारम्परिक स्वरूप को जिम्मेदार मान रहे हैं। लगातार एक ही फसल चक्र को दोहराना मिट्टी से उपयोगी खनिजों की कमी की वजह बना है। आवश्यक खनिजों की कमी की यह खौफनाक तस्वीर कृषि मंत्रालय की ओर से सूबे की मिट्टी के विभिन्न नमूनों के अध्ययन के दौरान सामने आई। गौरतलब है कि अभी हाल में राज्य के 95 विकास खंडों की 670 न्याय पंचायतों के मृदा उर्वरकता मानचित्र तैयार करते वक्त कृषि क्षेत्र की मृदा के तीन साल के नमूनों का उर्वरकता के लिहाज से गहन परीक्षण किया गया। इस अध्ययन के परिणाम के आधार पर ही पता चला कि सूबे की कृषि मृदा में आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फेट समेत विभिन्न खनिज तत्वों की भारी कमी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 0 से 40 प्रतिशत तक मिट्टी के नमूनों में जिंक और सल्फर, 0 से 20 फीसदी नमूनों में कॉपर और मैग्नीज, 0 से 60 प्रतिशत नमूनों में आयरन काफी कम मात्रा में पाया गया। कार्बन तत्व भी 2 से 0.5 तक कम देखा गया। गौरतलब है कि 65 प्रतिशत भू–भाग पर वनावरण तथा शेष बचे काफी बड़े भूभाग के दुर्गम होने की वजह से उत्तरांचल में कृषि तथा बागवानी का दायरा केवल दस प्रतिशत भूभाग पर ही सिमटा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल बोया जाने वाला क्षेत्रफल करीब आठ लाख हैक्टेयर है। राज्य के करीब 11 लाख वाशिंदे सीधे तौर पर खेती–बाड़ी से जुड़े हैं। इनमें लघु सीमांत काश्तकारों की तादाद नौ लाख के करीब है। प्रदेश के अपर सचिव (कृषि) के मुताबिक भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के प्रयासों के साथ ही काश्तकारों को स्थानीय स्तर पर उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत जल्द ही प्रदेश में कोर वैली सीड प्रोग्राम आरंभ किया जा रहा है।

अमर उजाला : फरवरी 20, 2005

बर्फ की चादर में छिपा है खजाना

इस साल पतित पावनी गंगा और यमुना में पानी की कमी नहीं रहेगी। जनवरी और फरवरी में सूबे के ऊपरी इलाकों में करीब 15 दिन हुए हिमपात का दूरगामी असर यह पड़ेगा कि नदियां सालभर पानी से लबालब तो रहेंगी ही, खेतों में हरियाली और बागानों में पेड़ फलों से लदे रहेंगे। यही नहीं, जल–विद्युत उत्पादन के बढ़ने से बिजली कटौती से निजात मिलने की भी उम्मीद है। इस मौसम में हुई बर्फवारी दो हिसाब से खास रही, एक तो इसका विस्तार कई क्षेत्रों

में था, दूसरे इसकी आवृत्ति भी ज्यादा रही। पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय रहने की वजह से ऊंची पहाड़ियों पर खासी बर्फबारी हुई है। भारत की ज्यादातर नदियों के स्नोफेड होने की वजह से साल भर पानी की तेज धार को बनाए रखने में बर्फबारी काफी फायदेमंद साबित होती है। गंगा, यमुना हो या रावी और व्यास सभी, स्नोफेड नदियां हैं मौसम में गर्मी आते ही धीरे–धीरे पिघलकर ये बर्फ नदियों में जाएगा, जिससे जलस्तर बढ़ेगा। यही नहीं, बर्फ के ऊपर ही बर्फ की नई परत जमते जाने से नीचे की बर्फ के लंबे समय तक सुरक्षित रहने की संभावना है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

अमर उजाला : फरवरी 22, 2005

विदेशियों को भायी उत्तरांचल की हर्बल और लीफ चाय

उत्तरांचल की पैदावार 'लीफ' और 'हर्बल' टी नामी गिरामी कंपनियों की चाय को टक्कर दे रही है। उत्तरांचल की चाय अब लोकल मार्केट में अपनी छाप छोड़ने के बाद देश–विदेश में पैठ बना रही है। अमेरिका, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, हालैंड, जर्मनी व जापान को 'उत्तरांचल चाय' का निर्यात किया जा रहा है। खासकर यूरोपीय देशों में उत्तरांचल चाय की सुगंधित और स्वादिष्ट 'हर्बल' व 'लीफ' टी की मांग बढ़ रही है। उत्तरांचल चाय की लोकप्रियता और डिमांड को देखते हुए चाय विकास बोर्ड ने आरगेनिक (जैविक) चाय की खेती का निर्णय लिया है। बोर्ड के मुताबिक शीघ्र ही कुमाऊं में छोटे–छोटे चाय प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में कौसानी, चौकोड़ी, विजयपुर, बेरीनाग, घोड़ाखाल, भीमताल के साथ ही गढ़वाल मंडल के कुछ स्थानों पर चाय का उत्पादन हो रहा है। घोड़ाखाल, बेरीनाग, चौकोड़ी व चंपावत में लाखों पौधों की नर्सरी स्थापित की गई है। इसके अलावा नैनीताल जिले के कोटाबाग, भवाली, पदमपुरी, धानाचुली और चंपावत जिले के लोहा, ललुवापानी में अव्वल दर्जे की चाय पैदा हो सकती है। अल्मोड़ा जिले में जलना, सोमेश्वर, दूनागिरी व नौधर को चाय बोर्ड द्वारा चाय पैदावार क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जा चुका है। कौसानी में दो करोड़ रूपये की लागत से चाय प्रसंस्करण इकाई स्थापित है। इस फैक्ट्री में 11 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। पिछले साल सूबे में 9000 किलो चाय उत्पाद हुआ था। चालू वित्त वर्ष में 20,000 किलो चाय उत्पादन का लक्ष्य है।

अमर उजाला : फरवरी 22, 2005

पिंडारी से पानी लाना व्यावहारिक नहीं

गर्मियों में जब भी कोसी नदी में पानी का जल स्तर गिरता है अल्मोड़ा में पिंडर नदी का पानी लाने की योजना पर चर्चा शुरू हो जाती है। जल निगम के अधिकारियों के मुताबिक पिंडर से अल्मोड़ा पानी लाने में कम से कम 175 किमी लंबी लाइन डाली जाएगी। इस योजना में लगभग 250 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इतने अधिक बजट और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के चलते जल निगम के इंजीनियरों ने इस योजना को अव्यवहारिक बताया है। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति कोसी नदी से होती है। इसका उद्‌गम हिमालय की किसी चोटी से नहीं है और यह नदी पूरी तरह जल स्त्रोतों पर आधारित है। इस कारण गर्मियों में इसमें पानी काफी कम हो जाता है। इन परिस्थितियों में यह बात उठती रही है कि भविष्य में यदि कोसी नदी का जल स्तर बहुत कम हो गया तो अल्मोड़ा वासियों को पानी कहां से मिलेगा, इसके लिए हिमालय में पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी से पानी की योजना बनाने की बात करीब दो दशक से उठती रही है। हालांकि यह योजना पिंडारी से यहां तक बन जाए तो इसमें कहीं पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगभग 175 किमी लंबी लाइन डालनी पड़ेगी जिसमें करीब 250 करोड़ रूपये की लागत आएगी। जल निगम सर्वेक्षण डिवीजन के अधिशासी अभियंता ने बताया कि पिंडारी से पानी लाने के लिए बीच में करीब 16 किमी इलाके में बर्फीली चट्टानें पड़ती हैं जिसमें लाइनें भी मुश्किल से डाली जा सकेंगी और यह क्षेत्र करीब छह माह तक बर्फ से ढंका रहता है। पिंडारी के जिस स्थान से पानी लाने की बात की जा रही है वहां भी जाड़ों में कभी इतना अधिक हिमपात होता है कि कई बार पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के बजाय सेराघाट से सरयू नदी पर आधारित योजना अधिक व्यावहारिक हो सकती है। इस योजना पर वर्तमान में 22 करोड़ रूपये लागत आने का आंकलन किया गया है। इसका प्रस्ताव भी शासन को गया है।

अमर उजाला : फरवरी 26, 2005

उत्तरांचल में महकेंगी दूसरे राज्यों की जड़ी–बूटियां

उत्तरांचल की वादियों में जल्द ही कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्किम, लेह–लद्‌दाख की जड़ी–बूटियों की खुशबू भी महकने लगेगी। दुर्लभ प्रजाति की जड़ी–बूटियों के संरक्षण को जीन बैंक स्थापित करने की योजना के तहत सरकार ने दूसरे प्रांतों की वनस्पतियों को भी लाने का निर्णय किया है। इससे जड़ी–बूटियों को विलुप्त होने से तो बचाया ही जा सकेगा, साथ में व्यावसायिक उत्पादन के लिए काश्तकारों को उन्नत किस्में भी मुहैया कराना मुमकिन होगा। वर्तमान में

प्रदेश में लेह के पुष्कर मूल तथा सिक्किम के चिरायते की करीब पचास हजार से भी ज्यादा पौध पनप चुकी है। गौरतलब है कि विश्व में प्रकृति की ओर तेजी से बढ़ते रूझान की वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में जड़ी–बूटियों का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में इस बाजार के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर पड़ोसी मुल्क चीन का कब्जा है। सरकार का मानना है कि 65 प्रतिशत वनावरण तथा जलवायु की विविधता की वजह से उत्तरांचल भी इस बाजार में मजबूती के साथ अपने लिए जगह तैयार कर सकता है। वर्तमान में प्रदेश में करीब तेरह सौ हैक्टेयर भूमि पर जड़ी–बूटियों की खेती की जा रही है। पौध तैयार करने के लिए करीब पांच सौ नर्सरियां स्थापित की गई हैं और मुनिकी रेती, कालाढूंगी, हर्षिल तथा सोमगाढ़ में हर्बल गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं। आरक्षित वनों में करीब 14 हजार हैक्टेयर क्षेत्र जड़ी–बूटियों के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

अमर उजाला : मई 2, 2005

बिना परमिट गोमुख जाने पर पाबंदी लगी

गंगोत्री धाम के ऊपरी क्षेत्रों में अब से बगैर विधिवत अनुमति के प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। गंगोत्री से आगे जाने के लिए यात्रियों को वन विभाग से परमिट लेना होगा और एक तय शुदा संख्या में ही लोग सफर कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास मौजूद एक–एक वस्तु का ब्यौरा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सफर के दौरान उपयोग की गई वस्तुओं के कचरे को भी साथ में लेकर लौटना होगा। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के संरक्षण के लिए सरकार गंगोत्री तथा यमनोत्री के मध्य के पर्वतीय क्षेत्र में विशिष्ट ब्रह्म कमल संरक्षण रिजर्व बनाने पर भी विचार कर रही है। सरकार का इरादा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का है। गंगोत्री से आगे जाने के लिए कड़ी शर्तें लागू होने का सीधा असर कांवड़ यात्रियों पर पड़ेगा। पिछले साल कांवड़ियों की संख्या 50 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। श्रद्धालुओं की इस लगातार बढ़ती तादाद का सीधा–सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। सभी पहलुओं के अध्ययन के पश्चात सरकार ने गंगोत्री धाम से आगे मानवीय गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने का निर्णय लिया है।

अमर उजाला : मई 1, 2005

अपने घर में ही मर रही हैं देश की प्रमुखतम नदियां

पहाड़ की कोख सूख रही है, तो मैदान में खुशहाली कहां से आएगी। मैदानी इलाकों को पानी के लिए पहाड़ों से निकलने वाली नदियों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। ताजा वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के 30 प्रतिशत जलस्त्रोत सूख गए हैं और भू–जलस्तर 30–60 फुट तक नीचे चला गया है। इससे मैदानी क्षेत्रों में भी जलस्तर औसतन 110 से 130 फुट तक नीचे चला गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीस सालों में आठ मीटर तक जलस्तर कम हुआ है। इस साल औसत से ज्यादा बर्फबारी होने और अन्य परिस्थितियों के सामान्य रहने के बावजूद गंगा के जल का डिस्चार्ज अपने पुराने स्तर पर नहीं लौटा है। मानक के मुताबिक मार्च से लेकर मई के दौरान औसत डिस्चार्ज 600 क्यूमेक्स प्रति सेकेंड होना चाहिए, जबकि अभी यह करीब 470 है। कुमाऊं में स्थित कोसी नदी का घटता जल प्रवाह भी स्थिति की भयावहता की ओर इशारा कर रहा है। जल संरक्षण को लेकर तरह–तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन संरक्षण से भू–जल दोहन का प्रतिशत ज्यादा है। जैसे–जैसे पानी नीचे जा रहा है, वैसे–वैसे जमीन की ऊपरी परत सिकुड़ती जा रही है। आई0आई0टी0 के हाइड्रोलॉजी विभाग के सरफेस वाटर विशेषज्ञ का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर उत्तरांचल जहॉं वनों की बहुतायत है, वहां भू–जल लगातार कम होने से दावानल की समस्या बढ़ती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में भू–जल की कमी से जमीन की ऊपरी सतह सिकुड़ने लगती है। और जमीन खेती के लायक नहीं रह जाती। राष्ट्रीय जल संस्थान के विशेषज्ञ के अनुसार इस साल तापमान पहले की अपेक्षा काफी कम होने से पहाड़ों पर पड़ी बर्फ पिघल नहीं पा रही है। भू–जल की कमी होने से जमीन के नीचे के पानी का जो रिसाव नदियों में होता था वह धीरे–धीरे कम होता जा रहा है, इससे भी जल स्तर घट रहा है।

अमर उजाला : मई 8, 2005

गन्ने के कैंसर पायरिला ने दी उत्तरांचल में दस्तक

गन्ने की किल्लत से जूझ रहे चीनी उद्योग के लिए एक और बुरी खबर। उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रहे पायरिला कीट ने उत्तरांचल में भी पांव पसार लिए है। प्रदेश के डोईवाला तथा हरिद्वार के कुछ हिस्सों में पायरिला को सक्रिय पाया गया है। गन्ने का कैंसर माने जाने वाला पायरिला कीट गन्ने की जड़ व तने के बीच आशियाना बनाता है और इस भाग से आवश्यक जल तथा अन्य पोषक तत्वों को चूस लेता है। इससे गन्ना पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। पायरिला की प्रदेश में आमद से सरकार की नींद उड़ी हुई है। प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने मुसीबत से निपटने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से संपर्क साधा है। प्रदेश में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र लगातार घट रहा है। वर्ष

2002 से अब तक प्रदेश में गन्ना उत्पादन क्षेत्र 17 हजार हैक्टेयर कम हो चुका है। प्रदेश में वर्ष 2002–03 में गन्ना क्षेत्र 1 लाख 27 हजार हैक्टेयर था, अब वह गिर कर 1 लाख 10 हजार पर सिमट चुका है। पायरिला को नष्ट करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है।

अमर उजाला : मई 9, 2005

प्रदेश भर में 1400 हेक्टेयर वन खाक

गर्मी बढ़ते ही दावाग्नि ने अब अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब तक राज्य का 1400 हेक्टेयर वन क्षेत्र दावाग्नि की भेंट चढ़ चुका है। इसमें करोड़ों की वन सम्पदा स्वाहा हो गयी है कुमाऊं में सबसे ज्यादा नुकसान पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा वन प्रभागों को हुआ है। जबकि गढ़वाल मंडल में केदारनाथ वन प्रभाग का शानदार चीड़ वन दावाग्नि की चपेट में आया है। नैनीताल वन प्रभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक दावाग्नि से सबसे ज्यादा नुकसान पिथौरागढ़ डिवीजन को हुआ है। पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 139.50 हेक्टेयर चीड़ वन दावाग्नि में जलकर खाक हो गया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटा 239 हेक्टेयर मिश्रित वन क्षेत्र भी दावाग्नि ने लील लिया है। इसमें बिन्सर का रिजर्व फारेस्ट भी शामिल है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में 53.50 हेक्टयर वन क्षेत्र व चंपावत वन प्रभाग में 29.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा बागेश्वर वन प्रभाग में 11.05 हेक्टेयर वन क्षेत्र दावाग्नि में जलकर खाक हो गया है। गढ़वाल मंडल में दावाग्नि से सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ डिवीजन को पहुंचा है। यहां 38 हेक्टेयर वन क्षेत्र रिजर्व फारेस्ट में खाक हुआ है तो 368 हेक्टेयर सिविल सोयम वन क्षेत्र भी दावाग्नि की भेंट चढ़ चुका है।

अमर उजाला : मई 29, 2005

कुदरत के कोप से 54 फीसदी घराटों की सांस बंद हुई

प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेश के तकरीबन 54 फीसदी घराट बंद हो गए हैं। सूबे के 11 जिलों में स्थापित 12,778 घराटों में से केवल अल्मोड़ा ही एक ऐसा जनपद है, जहां स्थापित सभी 2,150 घराट क्रियाशील हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अब इन घराटों की दशा सुधार कर उनके उच्चीकरण का बीड़ा उठाया गया है। इसके लिए उसने अनुदान दिए जाने की भी घोषणा की है। आधुनिक युग में लकड़ी के बने इन घराटों की महत्ता कम हो गई। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी घराट चलाए जा रहे हैं। आमतौर से घराटों का प्रयोग चक्की के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका मैकेनिकल प्रयोग भी किया जाता है। अब मैकेनिकल के साथ ही इसका इलेक्ट्रिकल प्रयोग किए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा घराट सुधारीकरण कार्यक्रम के तहत पांच किलोवाट तक विद्युत उत्पादन किए जाने पर एक लाख रूपये और मैकेनिकल उपयोग (ऑयल मिल, धान की कुट्टी आदि) पर 30,000 रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। उरेडा द्वारा इन दोनों प्रयोगों पर 6,000 रूपये का अनुदान है।

अमर उजाला : मई 28, 2005

चाय बनेगी विकास का आधार

गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश के उद्यान तथा लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि चाय उत्तरांचल के विकास का प्रमुख आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि चाय की खेती को व्यवसाय का रूप देने की जरूरत है। शुरूआत करने के छह साल बाद काश्तकारों को उत्पादन का लाभ मिलता है। इसे देखते हुए सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए अनुदान की व्यवस्था की है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री टोलिया ने कहा कि उत्तरांचल में उत्पादित चाय की काफी मांग है। यदि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का सहयोग मिले तो वनों की बंजर भूमि में भी चाय उगाई जा सकती है। उत्तरांचल में चाय को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय चाय बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पूरे विश्व में उत्तरांचल की चाय का अलग स्थान है। उत्तरांचल मे चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चाय बोर्ड ने कार्य योजना बनाई है जो शीघ्र लागू की जाएगी।

अमर उजाला : मई 30, 2005

धौलीगंगा की ग्रिड लाइन बिछाने में 77 सौ पेड़ कटेंगे

धौलीगंगा बिजली परियोजना के लिए बरेली ग्रिड तक हाईटेंशन लाइन बिछाने में 7706 पेड़ों के कटने की संभावना है। अभी तक 3331 पेड़ काटे जा चुके हैं। धौलीगंगा से बरेली तक लाइन बिछाने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है। राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लीलाराम शर्मा ने वन मंत्री को पूरा विवरण भेजा है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर भी इस महत्वपूर्ण मामले को अनदेखा करने का आरोप लगाया है।उन्होंने बताया कि 233 किलोमीटर लंबी लाइन में 538 टावर लगाए जाने हैं। लाइन बिछान में 7706 पेड़ों का कटना तय है। इसके अलावा कई स्थानों पर हरे पेड़ों के पास से लाइन ले जाई जा रही है लाइन पेड़ों की

ऊंचाई से लगती हुई है। वर्षा के समय पेड़ों के लाइन से छू जाने की आंशका है। इससे पेड़ों के सूख जाने और जंगली जानवरों के मरने की भी आंशका है।

अमर उजाला : जून 1, 2005

भूगर्भीय हलचलों से खिसक रही है हिमालय श्रृंखला

टेक्टॉनिक प्लेटों के 'मूवमेंट से वैज्ञानिकों ने लगभग तीन हजार किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला में अजीबो–गरीब परिवर्तन दर्ज किए हैं। भारत और तिब्बत सीमा से सटी यह पर्वत श्रृंखला जहां दक्षिण की तरफ खिसक रही है वही भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर–पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। भू–वैज्ञानिकों के मुताबिक लाखों वर्ष पूर्व इंडियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हिमालय श्रृंखला बनने के बाद एक बार फिर वही स्थिति पैदा होने जा रही है जब पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक हो जाएगा। दिल्ली और ल्हासा की दूरी में प्रतिवर्ष चार सेंटीमीटर तथा देहरादून से बदरीनाथ के बीच प्रतिवर्ष पंद्रह मिलीमीटर की कमी दर्ज होने के बाद इस बात को पुख्ता आधार मिल गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह परिवर्तन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का नतीजा हैं। अत्याधुनिक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से वैज्ञानिकों ने टेक्टॉनिक प्लेट्स के 'मूवमेंट' का बारीकी से अध्ययन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। टेक्टॉनिक प्लेटों की हलचल पर वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक डा. पी. बनर्जी की शोध रिपोर्ट में इंडियन और यूरेशियन प्लेट के एक–दूसरे से टकराने का जिक्र किया है। इंडियन प्लेट जहां उत्तर–पूर्व की तरफ बढ़ रही है वहीं यूरेशियन प्लेट दक्षिण की दिशा में खिसक रही है। टक्कर के बाद भी दोनों प्लेट का एक–दूसरे की तरफ बढ़ना जारी है। डा. बनर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराकर उसके नीचे जा रही है। आशंका है कि इस परिवर्तन से लाखों वर्ष बाद भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक सिर्फ और सिर्फ पर्वत श्रृंखलाएं ही नजर आएंगी। प्लेटों की इस हलचल से हिमालय पर्वत की ऊंचाई प्रतिवर्ष एक सेंटीमीटर बढ़ने का दावा भी वैज्ञानिकों ने किया है। भू–वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय क्षेत्र में होने वाले यह परिवर्तन लाखों वर्ष बाद ही सही, लेकिन इतिहास को दोहराएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक शायद तब तक मानव सभ्यता का अस्तित्व ही न रहे, लेकिन भारतीय महाद्वीप के अंतिम छोर तक सिर्फ पर्वत श्रृंखलाएं ही नजर आएंगी।

दैनिक जागरण : मई 28, 2005